

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 146
18 जुलाई, 2016 को उत्तर के लिए

स्पंज आयरन संयंत्र

146. श्री गोपाल शेटी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रचालित निजी और सरकारी क्षेत्र में स्पंज आयरन संयंत्रों की संख्या कितनी है;
- (ख) इन संयंत्रों में सृजित रोजगार संभावनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त संयंत्रों में स्थानीय लोगों को नौकरियों का कतिपय प्रतिशत प्रदान करने के लिए कोई उपबंध किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)

(क): वर्ष 2015-16 के दौरान देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के स्पंज आयरन संयंत्रों की संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है।

(ख) वर्ष 2012-13 में संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान घरेलू स्पंज आयरन बाजार में कुल रोजगार की संख्या 1,15,927 थी। राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-2 में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होने के नाते, सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में सीमित है जोकि उद्योग के निरंतर विकास और प्रतिस्पर्धात्मक प्रगति के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करती है। निजी इस्पात क्षेत्र में कर्मचारियों के भर्ती के संबंध में विशेष निर्णय व्यक्तिगत इस्पात कम्पनियों/निवेशकों द्वारा उनकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर लिए जाते हैं। सीपीएसयू के मामले में भर्ती सरकारी दिशा-निर्देशों पर आधारित होती है।

(लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 146 दिनांक 18 जुलाई, 2016)

अनुलग्नक- 1

भारतीय स्पंज आयरन उद्योग, 2015-16* का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	इकाईयों की संख्या
निजी क्षेत्र	
झारखंड	64
ओडिशा	83
पश्चिम बंगाल	41
छत्तीसगढ़	50
गोवा	3
गुजरात	1
महाराष्ट्र	8
आंध्र प्रदेश	7
कर्नाटक	31
तमिलनाडु	7
तेलंगाना	12
कुल निजी क्षेत्र	307
सार्वजनिक	
तेलंगाना	1
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	1
कुल: सार्वजनिक+ निजी	308

स्रोत: जेपीसी, * अनंतिम

अनुलग्नक - 2

भारतीय स्पंज आयरन उद्योग: 2012-13 में रोजगार

राज्य	रोजगार (संख्या)
झारखंड	5675
ओडिशा	51962
पश्चिम बंगाल	15998
छत्तीसगढ़	20990
गोवा	519
गुजरात	250
महाराष्ट्र	5246
आंध्र प्रदेश	5015
कर्नाटक	9496
तमिलनाडु	776
सकल योग	115927

स्रोत: जेपीसी सर्वेक्षण, 2012-13
